साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 08-14 जुलाई 2024 वर्ष-10, अंक-12
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

डिप्टी सीएम देवड़ा ने 3.65 लाख करोड़ का पेश किया बजट

मायूस किसान खुश

» बजट में पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी इजाफा

» लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के लिए 26,560 करोड़

» न पेट्रोल-डीजल पर कोई राहत और न ही कोई नया टैक्स लगाया

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। 3.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी अधिक है। बजट में जनता को पेट्रोल-डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। इसके साथ ही कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है। बजट में मोहन सरकार ने बेमौसम बारिश और प्रकृतिक आपदाओं से मायूस किसानों को खुश कर दिया है। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 11065 करोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही किसानों को गेहूं पर बोनस देने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने 30 करोड़ दिए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ और मृदा सरंक्षण के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया है। श्री अन्न के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए फेडरेशन के माध्यम से उपार्जित किए जा रहे कोदो-कुटकी पर प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।

-मोहन सरकार में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रावधान

-उज्जैन में चना व ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की होगी स्थापना

-गाय का तीन गुना बढ़ाया बजट, गौवंश रक्षा वर्ष मनाएगी सरकार

-सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 या 8 लेन के होंगे

वर्षवार-बजट करोड़ में	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
	2,05,398	2,41,375	2,79,237	3,14,025	3,65,067

खुला पिटारा

» शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़
» स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़
» खेल के लिए 586 करोड़
» तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़
» वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़
» दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़
» गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए
» संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़
» उद्योग विभाग के लिए 4 हजार करोड़
» स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़
» सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़
» 520 करोड़ पशुपालकों के लिए दिया
» उज्जवला योजना के लिए 520 करोड़
» पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़
» पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़
» मृदा सरंक्षण के लिए 30 करोड़ रुपए
» प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने 30 करोड़
» पीएम उषा परियोजना के लिए 565 करोड़
» 247 महाविद्यालयों के लिए 244 करोड़
» किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपए
» ऊर्जा के लिए 14 हजार करोड़ का प्रावधान
» अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 11065 करोड़
» गेहूं पर बोनस देने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
» सीएम राइस विद्यालयों के लिए 2737 करोड़ रुपए
» आंगनबाड़ी भवनों के लिए फिर 100 करोड़ रुपए
» महिला-बाल विकास विभाग के लिए 26560 करोड़
» जनमन योजना के लिए 1607 करोड़ का प्रावधान
» कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4421 करोड़
» मनरेगा के लिए बजट में 3500 करोड़ रखे गए
» ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़ रुपए
» सड़कों के नवीनीकरण के लिए 900 करोड़ रुपए
» प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़
» नगरीय विकास के लिए 16744 करोड़ रुपए
» सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 2400 करोड़
» पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़
» अस्पताल और औषधालय के लिए 1680 करोड़
» जिला मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए 1500 करोड़
» जिला माइनिंग फंड के लिए 1300 करोड़ का प्रावधान
» आपदा प्रबंधन के लिए 1193 करोड़ का प्रावधान
» विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1167 करोड़
» मेट्रो रेल के लिए 1160 करोड़ रुपए का प्रावधान
» केन्द्रीय सड़क निधि के लिए 1150 करोड़ का प्रावधान
» इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़
» हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1020 करोड़ का प्रावधान
» सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के लिए 1000 करोड़
» जनजाति इलाके के लिए विकास के लिए 40800 करोड़ का प्रावधान

» मिलेट्स को बढ़ावा देने डिंडोरी में श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा
» मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया
» 900 किमी का नर्मदा प्रगति, अटल प्रगति पथ 550 विंध्य एक्सप्रेस वे प्रस्तावित
» पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1 हजार सड़क का निर्माण प्रस्तावित
» सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
» इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चालई जाएंगी
» सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के लिए शुरुआती स्तर पर 500 करोड़
» अब नर्मदापुरम, शहडोल, बालाघाट, सागर और मुरैना में भी आयुर्वेद अस्पताल खुलेंगे

जनता को समर्पित

मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। ये बजट सर्वस्पर्शी है। जनता का बजट है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है।

जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम

सर्वे भवंतु सुखिनः

मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश बजट भाजपा सरकार के सर्वे भवंतु सुखिनः के संकल्प को दर्शाता है। यह बजट मध्यप्रदेश की सशक्ति, समृद्धि और जनकल्याण के संकल्पों की सिद्धि का प्रतीक है। जनकल्याण कारी बजट से प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का होगा और विस्तार होगा। इस बजट में हर वर्ग से ख्याल रखा गया है।

वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

सभी वर्गों का ध्यान

प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया। सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है। सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है।

डॉ. मोहन यादव, सीएम

सरकार के दो बजट

मप्र सरकार के दो बजट हैं। एक बजट जो सरकार को जनता को बताना है। डॉ. मोहन यादव सरकार का यह दूसरा बजट आया है। सरकार वे अपने संकल्प पत्र के वादे अनुसार कोई काम नहीं किया। मप्र में तीन सी की सरकार है, जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना नाता जोड़ा है।

जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ

बजट के मुख्य बिन्दु

» मध्यप्रदेश के हर घर नल से जल पहुंचने का लक्ष्य।
» मध्यप्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे
» सरकार के प्रयासों से 14 मेडिकल कॉलेज संचालित
» प्रदेश में 22 नए आईटीआई संस्थान शुरू किए जाएंगे
» पुलिस में 7500 पदों पर होगी भर्ती।
» खाद्य प्रसंस्करण के लिए खास प्रावधान।
» गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का किया काम
» कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना

विधानसभा में हंगामे के बीच देवड़ा ने पेश किया प्रदेश का बजट

चलित पशु कल्याण सेवा में खर्च होंगे 82 करोड़

पीएम श्री योजना अंतर्गत शुरू किए जाएंगे 22 नए छात्रावास

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। मोहन सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए खजाना खोला है। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा है। अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। दोनों ओर औद्योगिक कॉरीडोर विकसित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। पीएम ग्राम सड़क के अंतर्गत 2024-25 में 1,000 किमी सड़क बनाएंगे और 2,000 किमी सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य है। अमरकंटक एवं सतपुडा ताप विद्युत गृहों में 660-660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण होगा। 603 सर्किट किमी पारेषण लाइनों एवं 2,908 मेगावाट क्षमता के अति उच्च दाब उपकेन्द्र के कार्य प्रस्तावित हैं। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1,42,565 रुपए रही, जो 2003-04 की 13,465 रुपए से लगभग 11 गुना हो गई है। नीति आयोग की जनवरी-2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच मप्र के 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट एवं एमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक 1500 प्री-स्कूल क्लासेस संचालित कर रहे हैं। 2024-25 में 3,200 प्राथमिक शालाओं में प्री-स्कूल शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। 730 स्कूलों को पीएम श्री योजना अंतर्गत चिन्हित किया है। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के साथ भौतिक संसाधनों का उन्नयन भी किया जाएगा। प्रदेश के बैगा, भारिया, सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नए छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे।

पशु चिकित्सा पर सरकार का फोकस

संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रखे हैं। यह 2023-24 के मुकाबले 250 प्रतिशत अधिक है। भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथ गमन किया। राज्य की सीमाओं के अंतर्गत राम पथ गमन के अंचलों के स्थलों को चिह्नांकित कर उनका विकास करेंगे। सीएम ने श्री कृष्ण पाथेय योजना की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश में श्री कृष्ण पथ के पुनरावेषण और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य, संस्कृति तथा संस्कार का संरक्षण किया जाएगा। मई 2023 से प्रारंभ 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों ने अब तक 5.46 लाख से अधिक पशुओं को घर पर चिकित्सा सुविधा दी है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में 82 करोड़ खर्च होंगे।

- केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ अधिक मिलेंगे
- उज्जैन और जबलपुर को केंद्र से मिलेंगे 270 करोड़
- गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की नई योजना होगी शुरू
- रसोइयों का मानदेय 400 प्रति माह से बढ़कर 3400 किया

मधुमक्खी पालन पर फोकस

मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन की स्थापना पर फोकस। किसानों की आय बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को पांच वर्ष तक मंडी शुल्क में शत-प्रतिशत तथा विद्युत टैरिफ में एक रुपए प्रति यूनिट की छूट। प्रदेश में उपलब्ध 4 लाख 42 हजार हैक्टेयर जलक्षेत्र में से 4 लाख 40 हजार हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3 लाख 82 हजार मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।

पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना

2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी लिंक परियोजना से 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। पेयजल मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना और के लिए प्रावधान किए गए।

नगरीय विकास के लिए 16744 करोड़

नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी के माध्यम से दो संरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए नगर वनीकरण योजना लागू की जाएगी। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ आयोजित होगा। इसके लिए 10 जिलों में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उज्जैन तथा जबलपुर शहर को आगामी तीन वर्ष में केंद्र सरकार से 270 करोड़ रुपए मिलेंगे।

लाड़ली बहना की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना| लाड़ली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 48 लाख 3000 बालिकाओं को लाभ मिल रहा है। लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना योजना के लिए 26560 करोड़ का प्रावधान, कन्या विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उज्जैन का हर मार्ग आठ लेन होगा| मध्य प्रदेश में अगले पांच साल में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किमी का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ बनाया जाएगा। दोनों ओर औद्योगिक कॉरीडोर विकसित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में बायपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को चार लेन अथवा आठ लेन किया जाएगा।

छह शहरों का ई-बस| देवड़ा ने बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की हैं, उनमें पीएम ई-बस योजनांतर्गत छह शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में केंद्र सरकार की सहायता से 552 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पांच साल में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है, जो 2023-24 के 3,14,025 करोड़ के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है।

किस क्षेत्र में कितना बढ़ा बजट| कृषि क्षेत्र का बजट 15 प्रतिशत, स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा में चार प्रतिशत, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों की योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 9 प्रतिशत, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए 13 प्रतिशत, संस्कृति संवर्धन के लिए 35 प्रतिशत, रोजगार के लिए 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

प्रदेश में कोई नया कर नहीं| शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान के परिपेक्ष में पुनरीक्षण के लिए समिति का प्रतिवेदन मिल गया है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य नीति के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है। बजट में किसी तरह का कोई नया कर अधिरोपित नहीं करने वह कर नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव है।

प्रति व्यक्ति आय 10 हजार बढ़ी| विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 10,055 रुपए की बढ़त हुई है। यह सालाना एक लाख 42 हजार 565 रुपए पर पहुंच गई है। इसके पहले यह एक लाख 32 हजार 10 रुपये थी। यह प्रदेश में बढ़ती अर्थव्यवस्था के संकेत बताए जा रहा है।

प्रदेश में और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे| स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी। कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोतर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45फीसदी ज्यादा हैं।

मप्र को नई ऊर्जा

पीएम नरेन्द्र मोदी के दक्ष नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा जो विकास की गति को तेज करेगा।

राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी सीएम

सबका होगा विकास

बजट मध्यप्रदेश में निवास करने वाले सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए बनाया गया एक बेहतरीन बजट है। इसमें प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिये क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। बजट पर अमल से हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा। बजट में गांवों और किसानों के साथ प्रदेश के शहरों के विकास के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं।

कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री

अतुलनीय बजट

2024-25 समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक अतुलनीय बजट है। इस बजट में हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, युवा, वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों सभी के समग्र विकास एवं कल्याण की चिंता की है। जन, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ-साथ इनके संवर्धन के लिए भी हमारी सरकार ने शिद्दत से प्रयास किए है। विकास के प्रकाश से अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा।

विजय शाह, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री

गरीब-किसान को सुरक्षा

वर्ष 2024-25 का बजट प्रदेश में विकास तथा जनता के जीवन में सहजता लाने वाला, जन-हितैषी बजट है। युवा व महिला सशक्तिकरण के साथ प्रदेश की सुदृढ़ अधोसंरचना, किसान, गरीब, मजबूर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला बजट है। गरीब परिवार की बेटियों के सम्मानपूर्वक विवाह के लिए सीएम कन्यादान विवाह योजना राशि में तीन गुना वृद्धि कर 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नारायण सिंह कुशवाह,खाद्य प्र-संस्करण मंत्री

सिंचाई पर फोकस

बजट वर्ष 2024-25 में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं और नए कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। बजट में सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड, केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए 200 करोड़, बांध तथा नहरों के लिए 116 करोड़, नहरों और तालाबों के लिए 110 करोड का प्रावधान किया गया है।

तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री

सर्वहारा वर्ग का कल्याण

बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। सीएम डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाए इस बजट में युवाओं, किसानों और गरीबों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 19 हजार 406 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में एक हजार 46 करोड़ ज्यादा है। गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री

पांच जिलों में होंगे आयुर्वेद कॉलेज

गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा की शुरुआत भी की गई है। 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी शुरू किया गया है। बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21 हजार 444 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 34 फीसदी ज्यादा है।

सीएम राइज स्कूलों में परिवहन व्यवस्था

2024-25 में 150 सीएम राइज स्कूल नवीन भवन में संचालित होंगे। इन विद्यालयों में एक किलोमीटर से अधिक दूर रहे बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज विद्यालयों के लिए 2737 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 में 3200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की जाएगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है। पीएम श्री योजना अंतर्गत 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। 87 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ पुस्तक और गणेश दिए जाएंगे।

प्रदेश में हो रहा औद्योगिक विकास

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। राज्य ने ऑटोमोबाइल, वस्त्र, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, फॉर्मा, अक्षय ऊर्जा, वेयरहाउसिंग को ऐसे ट्रस्ट सेक्टर के रूप में चिह्नित किया है। यह आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करते हैं। उज्जैन में प्रथम रीजनल इंडस्ट्री में लगभग 12170 करोड़ रुपए का निवेश और 26000 से अधिक नवीन रोजगार उपलब्ध होना संभावित है।

जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। उद्योग क्षेत्र के लिए 4190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास के लिए 27870 करोड़ का बजट रखा गया है। हर साल जल गंगा संवर्धन अभियान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है। मध्यान भोजन 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रसोइयों का मानदेय 400 रुपए प्रति माह से बढ़कर 3400 किया गया है।

30 फीसदी तक घट जाएगा यूरिया का खर्च

अरहर में डालें ये लिक्विड बायोफर्टिलाइजर

भोपाल। जागत गांव हमार

दलहनी फसलों के स्थान पर सोयाबीन का रकबा बढ़ने से दलहनी फसलों का रकबा घट रहा है। वहीं अरहर की फसल का रकबा उपजाऊ मैदानी भूमि से हटकर थोड़ी ढलान वाली, कम उपजाऊ भूमि की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आ रही है। लेकिन अरहर की फसल के विस्तृत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अधिक उत्पादन क्षमता वाली उकटारोधी किस्मों के उपयोग से उत्पादकता में उतार-चढ़ाव कम हुआ है और उत्पादकता में स्थिरता आई है। सिंचाई, उर्वरकों और कृषि रसायनों के उपयोग के प्रति किसानों की बढ़ती जागरूकता दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। समय पर बुवाई, पौधों की पर्याप्त संख्या, राइजोबियम कल्चर और कवकनाशी दवाओं से बीजोपचार और खरपतवार प्रबंधन के साथ ही बिना लागत या न्यूनतम निवेश वाले ऐसे इनपुट भी उत्पादकता बढ़ाते हैं। अरहर की आसमान छूती कीमत के कारण किसानों का रुझान फिर से अरहर की खेती की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इसकी खेती से अधिक उपज लेने और खर्च को कम करने के लिए लिक्विड बायोफर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसकी मदद से किसानों को काफी फायदा भी हो रहा है।

लिक्विड बायोफर्टिलाइजर का इस्तेमाल| अरहर के लिए राइजोबियम जैव उर्वरक जिसे राइजो-1 के नाम से भी जाना जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें इसे अरहर की फसल के लिए आईसीएआर के द्वारा तैयार किया गया है। राइजो-1, एक तरल जैव उर्वरक है, जो 30 तक नाइट्रोजन उर्वरक बचाता है। बीज टीकाकरण (10 मिली/किग्रा बीज) अनाज की उपज को 10-15 तक बढ़ाता है। साथ ही उत्पाद में 108-1011 कोशिकाएं/एमएल होती हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ कमरे के तापमान पर एक वर्ष होती है।

भूमि का चयन और तैयारी| अरहर की फसल के लिए मध्यम से भारी काली मिट्टी, उचित जल निकास वाली और पीएच मान 7.0-8.5 सबसे अच्छी होती है। खेत की दो-तीन बार देशी हल या ट्रैक्टर से गहरी जुताई करें और हल चलाकर खेत को समतल कर लें। जल निकास की उचित व्यवस्था करें।

इन किस्मों का करें चयन| बहु-फसल प्रणाली में या यदि थोड़ी ढलान वाली असिंचित भूमि हो तो शीघ्र पकने वाली किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। उपास-120 (1976), आईसीपीएल-87 (प्रगति,1986), ट्रामबे जवाहर तुवर-501 (2008), जे.के.एम.-7 (1996), जे.के.एम.189 (2006), आई.सी.पी.-8863(मारुती,1986), जवाहर अरहर-4(1990)

बुवाई का समय और तरीका

अरहर की बुवाई वर्षा प्रारम्भ होते ही कर देनी चाहिए। सामान्यत: बुवाई जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक करनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेमी तथा मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों के लिए 70 से 90 सेमी होनी चाहिए। कम अवधि वाली किस्मों के लिए पौधों के बीच की दूरी 15-20 सेमी तथा मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों के लिए 25-30 सेमी होनी चाहिए।

बीज की मात्रा और उपचार

शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 20-25 किग्रा तथा मध्यम पकने वाली किस्मों के लिए 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई करनी चाहिए। चैफली विधि से बुवाई करने पर प्रति हेक्टेयर 3-4 किग्रा बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम थाइरम 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम या विटावैक्स 2 ग्राम 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। उपचारित बीजों को राइजोबियम कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें तथा फिर रोपण करें।

15 संस्थानों के साथ मिलकर 245 लाख एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य

देशभर में इफको 300 नमो ड्रोन दीदी और ड्रोन उद्यमी बना रहा

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद-बीज बिक्री करने वाली सरकारी संस्था इफको 300 नमो ड्रोन दीदी और ड्रोन उद्यमियों को तैयार कर रहा है और देशभर के चयनित किसानों की 245 लाख एकड़ फसल को ड्रोन के जरिए छिड़काव करने का टारगेट रखा गया है। इफको ने इसके लिए 15 संस्थानों से हाथ मिलाया है। बता दें कि सरकार के कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल और विकास कार्यक्रम को इफको संभाल रहा है। फसलों के छिड़काव टारगेट को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर ड्रोन के ऑर्डर भी दिए गए हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए इफको ने जुलाई से नैनो उर्वरक के प्रमोशन के लिए संवर्धन महाअभियान की शुरुआत भी की है। नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 2024 से देशभर में नैनो उर्वरक संवर्धन महाअभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत इफको ने 200 मॉडल नैनो ग्राम समूहों का चयन भी किया है। जिसके तहत 800 गांवों के किसानों को इफको की नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी एवं सागरिका के मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही इफको ड्रोन उद्यमियों को तैयार कर रही है जिन्हें 100 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसान कम दरों पर छिड़काव की सुविधा उठा सकें।

देश के 513 जिलों में नैनों उर्वरकों का परीक्षण होगा - नैनो उर्वरकों का खेती में प्रयोग बढ़ाने के लिए देश के 413 जिलों में नैनो डीएपी (लिक्विड) के 1270 कार्यक्रम और 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस (लिक्विड) के 200 परीक्षण किए जाएंगे। इफको की ओर से नैनो उर्वरकों को सहकारी समिति और अन्य बिक्री केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर नैनो उर्वरकों के लाभ के बारे में किसानों को बताया जाएगा। नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए इफको की ओर से एग्रीकल्चर ड्रोन किसानों को दिए जा रहे हैं। 245 लाख एकड़ क्षेत्र पर ड्रोन से छिड़काव के लिए 15 संस्थानों से हाथ मिलाया है। जो किसानों के खेतों में छिड़काव करेंगे। प्रत्येक खेत में छिड़काव पर 100 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

3 साल में 7 करोड़ नैनो यूरिया का इस्तेमाल हुआ

इफको के अनुसार अगस्त 2021 से 26 जून 2024 तक इफको के जरिए बनाई गई कुल 7.55 करोड़ नैनो यूरिया और 0.69 करोड़ नैनो डीएपी का इस्तेमाल किसान कर चुके हैं। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इफको ने वर्ष 2024-25 में 4 करोड़ नैनो यूरिया प्लस और 2 करोड़ नैनो डीएपी बोतलों के उत्पादन का टारगेट बनाया है। वहीं, 1 जुलाई से शुरू हुए अभियान के दौरान नैनो उर्वरकों की 6 करोड़ बोतलें उपलब्ध कराने की योजना है और इनका वितरण इफको की 36000 सदस्य सहकारी समितियों के जरिए किया जाएगा।

300 नमो ड्रोन दीदी और ड्रोन उद्यमी

इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर यूएस अवस्थी के अनुसार नैनो उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन कैंपेन हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए इफको की ओर से 2500 कृषि ड्रोन किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा रहे हैं जिसके लिए 300 'नमो ड्रोन दीदी' तथा ड्रोन उद्यमी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा कई तरह के स्प्रेयर भी उपलब्ध कराए गए हैं जिसके माध्यम से किसान आसानी से अपने खेतों में नैनो उर्वरकों का छिड़काव कर सकेंगे

झारखंड में शिवराज सिंह चौहान बोले

पीएम मोदी का संकल्प हर गरीब बहन को लखपति बनाना लक्ष्य

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय झारखंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निर्माणधीन आवासों का निरीक्षण किया। साथ ही, स्व-सहायता समूह की बहनों से लखपति दीदी अभियान के संबंध में चर्चा की। उन्होंने डीआरएफ पद्धति से बन रही सड़कों का निरीक्षण भी किया। चौहान ने झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित ग्राम सुगिया का दौरा किया और लोगों से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा कर समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के रामगढ़ जिले में स्व-सहायता समूह की बहनों से भेंट कर बातचीत की। इस दौरान बहनों ने शिवराज सिंह को तिलक लगाकर पारंपरिक स्वागत किया। साथ ही स्व-सहायता समूह की बहनों ने मिट्टी के सांचे से बने पीतल के बर्तन भी शिवराज सिंह को दिखाए और अपने अनुभव साझा किए। बहनों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि बहनों को मजबूर नहीं, मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हर गरीब बहन को लखपति बनाना है और दीदी अपने परिश्रम से इसे पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। लखपति दीदी मतलब घर का कामकाज करते हुए हर बहन की सालाना आय एक लाख रुपए से अधिक हो।

पीएम आवास का निरीक्षण

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के रामगढ़ जिले के ग्राम सुगिया में पीएम जन-मन योजना के अंतर्गत रिंकी देवी के निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण कर उनसे चर्चा की। इस दौरान चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है। स्वयं का पक्का मकान बनने पर कितनी खुशी होती है, वो इस परिवार के चेहरे पर देखी जा सकती है।

झारखंड में बालू, ईंट महंगी

केंद्रीय गमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड प्रवास के दौरान ग्राम सुगिया का भ्रमण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं के संबंध में उनसे बात करते हुए बताया कि उन्हें ग्रामीण आवास के मकान स्वीकृत हो गए, किस्त भी आ गई, लेकिन झारखंड में बालू ईंट बहुत महंगी है, खरीद नहीं पा रहे हैं, इस कारण मकान बनाने में समस्या हो रही है।

एफडीआर पद्धति से बनी सड़क का निरीक्षण

केंद्रीय मंत्री चौहान ने झारखंड के रामगढ़ में एफडीआर पद्धति से बनी सड़क का निरीक्षण किया और मजदूरों से इस संबंध में चर्चा की। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) एक रिसाइकिलिंग पद्धति है, इसमें बहुत ही कम संसाधनों में टिकाऊ सड़कें बनाई जा सकती हैं। खराब हो चुकी पक्की सड़क को उखाड़कर उससे निकलने वाले मटेरियल को पहले प्लांट ले जाया जाता है, फिर उसमें केमिकल और आवश्यक सामग्री मिलाकर नया मटेरियल तैयार किया जाता है और फिर उसे सड़क पर डाला जाता है। सड़क की धूल को हवा के प्रेशर से अच्छी तरह से साफ करने के बाद उस पर फैलिक कपड़े को बिछाया जाता है, ताकि वह मॉइस्चराइजर्स को आब्जर्व कर सके। इसके बाद उसके ऊपर डामर के लेप का छिड़काव किया जाता है और फिर मटेरियल को उस पर डालकर रोलर को घुमाया जाता है। इस पद्धति से बनने वाली सड़कें, आम सड़क से कई गुना मजबूत और सस्ती हैं।

अब 18 महीने पहले ही लग जाएगा अल नीनो का पता

अल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) भारत समेत पूरे एशिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में हवाओं, मौसम और समुद्र के तापमान में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। यह सूखे, बाढ़, फसलों की हानि और भोजन की कमी का कारण बन सकता है।हम सब ने 2023-2024 में अलनीनो की घटना महसूस की, जिसने दुनिया भर के मौसम, जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर भारी असर डाला।

मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय के महासागर और पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल (एसओईएसटी) के शोधकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक नया मॉडल विकसित किया है। इसकी मदद से वे 18 महीने पहले तक ईएनएसओ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे पारंपरिक जलवायु मॉडल पूर्वानुमान में काफी सुधार हो सकता है।

शोधकर्ताओं के महासागर और वायुमंडल को लेकर सटीक पूवानज़ुमान लगाने वाले निष्कर्ष नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, नया मॉडल जिसे उन्होंने विस्तारित नॉनलीनियर रिचार्ज ऑसिलेटर (एक्सआरओ) मॉडल नाम दिया गया है। यह एक साल से अधिक समय पहले ईएनएसओ घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में भारी सुधार कर सकता है, जो दुनिया भर के लवायु मॉडल से बेहतर है और सबसे कुशल एआई पूर्वानुमानों के बराबर है।

शोध के मुताबिक, यह मॉडल ईएनएसओ के मूलभूत भौतिकी और वैश्विक महासागरों में अन्य जलवायु पैटर्न के साथ ईएनएसओ की आंतरिक क्रियाओं को प्रभावी ढंग से शामिल करता है जो मौसम दर मौसम बदलते रहते हैं।

वैज्ञानिक दशकों से ईएनएसओ के वैश्विक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को देखते हुए इसके पूवानज़ुमानों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पारंपरिक तरीके से पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल एक वर्ष से अधिक समय के साथ ईएनएसओ का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान लगाने में संघर्ष करते रहे हैं।

एआई नए पूर्वानुमान की सटीकता में भारी सुधार करने में मदद करता है

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में हाल ही में हुई प्रगति ने इन सीमाओं को आगे बढ़ाया है, जिससे 16 से 18 महीने पहले तक सटीक पूर्वानुमान हासिल हुए हैं।

शोध के मुताबिक, एआई मॉडल में पूर्वानुमान के स्रोत की जांच पड़ताल करने में सक्षम न होने के कारण कम विश्वास होता है कि ये भविष्य की घटनाओं के लिए सफल होंगे क्योंकि पृथ्वी गर्म होती जा रही है, जिससे महासागरों और वायुमंडल में धाराएं बदल रही हैं।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से बताया, एआई मॉडल की प्रकृति के विपरीत, हमारा एक्सआरओ मॉडल भूमध्यरेखीय प्रशांत रिचार्ज-डिस्चार्ज भौतिकी के तंत्र और उष्णकटिबंधीय प्रशांत के बाहर अन्य जलवायु पैटर्न के साथ इसकी आंतरिक

क्रियाओं के बारे में एक पारदर्शी नजरिया प्रदान करता है।

अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय प्रशांत, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर और अटलांटिक की शुरुआती अवस्थाएं अलग-अलग मौसमों में ईएनएसओ के पूर्वानुमान को बढ़ाती हैं। पहली बार, हम ईएनएसओ के पूर्वानुमान पर उनके प्रभाव को मजबूती से मापने में सक्षम हैं, इस प्रकार ईएनएसओ भौतिकी और इसके पूर्वानुमान के तीतों के बारे में जानकारी बढ़ जाती है।

जलवायु मॉडल की कमियों में सुधार: शोध के अनुसार, इसके निष्कर्ष जलवायु मॉडल की नवीनतम पीढ़ी में कमियों की भी पहचान करते हैं, जिसके कारण ईएनएसओ का सटीक पूर्वानुमान लगाने में वे विफल हो जाते हैं।

ईएनएसओ पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए, जलवायु मॉडल को ईएनएसओ के मुख्य भौतिकी को सही ढंग से समझना चाहिए और इसके अतिरिक्त, वैश्विक महासागरों में अन्य जलवायु पैटर्न के तीन मिश्रित पहलुओं को भी समझना चाहिए: ईएनएसओ पूर्वानुमान शुरू होने पर इनमें से प्रत्येक जलवायु पैटर्न की स्थिति का सटीक जानकारी, इनमें से प्रत्येक जलवायु पैटर्न की सही मौसमी रूप से बदलती 'महासागर स्मृति' और इन अन्य जलवायु पैटर्न में से प्रत्येक अलग-अलग मौसमों में ईएनएसओ को कैसे प्रभावित करता है, इसका सही तरीका।

शोध के मुताबिक, अल नीनो के अतिरिक्त, नया एक्सआरओ मॉडल उष्णकटिबंधीय हिंद और अटलांटिक महासागरों में अन्य जलवायु में होने वाले बदलाव के पूर्वानुमान में भी सुधार करता है, जैसे कि हिंद महासागर डिपोल, जो अल नीनो के प्रभावों से परे स्थानीय और वैश्विक मौसम पैटर्न को भारी तौर पर बदल सकता है।

भविष्य में और सटीक होगा पूर्वानुमान: शोध में कहा गया है कि यह ईएनएसओ की अधिक सटीक और लंबी अवधि के पूर्वानुमान और वैश्विक जलवायु मॉडल में सुधार का अवसर प्रदान करता है।

हालांकि ईएनएसओ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में होती है, लेकिन अब हम इसे केवल उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की समस्या के रूप में नहीं सोच सकते, चाहे मॉडलिंग और पूर्वानुमान के जरिए से या अवलोकन के नजरिए से। वैश्विक उष्णकटिबंधीय और उच्च अक्षांश मौसमी जलवायु पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए अहम हैं।

मॉडल की कमियों का पता लगाकर, जलवायु पैटर्न की आंतरिक क्रियाओं को समझ कर, हम अपने वैश्विक जलवायु मॉडल को काफी हद तक बदल सकते हैं।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा कि, इससे वैश्विक जलवायु मॉडल की अगली पीढ़ी के लिए इन निष्कर्षों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जलवायु में बदलाव के प्रभावों का पूवानज़ुमान लगाने और उन्हें कम करने के हमारे नजरिए में सुधार होगा। ऐसी प्रगति सामाजिक तैयारियों और जलवायु-संबंधी खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

फसलों के लिए और खतरनाक हो सकती हैं टिड्डियां

टिड्डियां गंध की मदद से फसलों को पहले से बेहतर तरीके से पहचान रही हैं तथा उनके अनुसार अपने आपको ढाल रही हैं। इस काम को वे अरबों से ज्यादा जीवों के झुंड में आसानी से कर सकती हैं। इस चिंताजनक बात का खुलासा यूनिवर्सिटी ऑफ कोंस्टांज के क्लस्टर ऑफएक्सीलेंस कलेक्टिव बिहेवियर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। शोध के मुताबिक, चार साल पहले जब केन्या में टिड्डियों का प्रकोप फैला था, टिड्डियों ने कुछ इलाकों में फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। टिड्डियों के वहां से चले जाने के बाद केवल जहरीले पौधे ही बच पाए थे।

शोधकर्ताओं ने इस प्रकोप के दौरान क्षेत्र से आंकड़े एकत्र किए और उनके आधार पर प्रयोगों और मॉडलों की योजना बनाई। उनका उद्देश्य टिड्डियों के रहस्यों को उजागर करना था, जो एक वैश्विक खतरा है, इसके कारण धरती पर 10 में से एक व्यक्ति प्रभावित होता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि एक अरब टिड्डियों का झुंड एक दिन में लगभग 1,500 टन भोजन चट कर जाता है, जो 2,500 लोगों की रोजमर्रा के भोजन के बराबर है। ये चौंका देने वाले आंकड़े उनके शोध की तात्कालिकता और महत्व को उजागर करते हैं।

अकेले और झुंड में रहने वाले जानवरों के बीच काफी अंतर: टिड्डे हमेशा झुंड में नहीं रहते हैं। टिड्डे, टिड्डे होते हैं जो कुछ ही घंटों में अकेले रहने के बावजूद भी झुंड में बदल सकते हैं। अवस्था के इस परिवर्तन का व्यवहार, विकास, शरीर क्रिया विज्ञान और प्रजनन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र और शरीर के रंग में भी बदलाव दिखाई देते हैं, जो छलावरण वाले हरे रंग से बदलकर एक आकषज्क पीले-काले रंग में बदल जाता है।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से जीवन शैली में यह अत्यधिक परिवर्तन जानवरों के भोजन की खोज करने के तरीके को प्रभावित करता है, साथ ही भोजन की तलाश करते समय जानवरों के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। इसलिए, उन्होंने प्रयोगशाला में अकेले रहने वाले और मिलनसार जानवरों के भोजन की तलाश के निणज्यों की निगरानी के लिए व्यावहारिक प्रयोग किए।

भोजन के विकल्पों को दृष्टि से या घ्राण द्वारा या संयोजन में देखा जा सकता है। यहां बताते चले की 'घ्राण पिण्ड' सूंघने की क्षमता के लिए जाना जाता है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, व्यवहारिक प्रयोगों और निर्णय लेने के मॉडल के आधार पर, हमने पाया कि भोजन की खोज करते समय झुंड में रहने वाले जानवरों में गंध की भावना बेहद महत्वपूर्ण होती है।

जानवरों की घ्राण प्रणाली अहम: इसलिए, शोध दल को पता था कि घ्राण प्रणाली अहम है। नतीजतन, उन्होंने इन विवो कैल्शियम इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके गंध प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के क्षेत्र पर करीब से नजर डाली। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के पूरे क्षेत्रों में सूचना प्रसंस्करण को दर्शाती है।

शोध के मुताबिक परिणाम स्पष्ट थे, यदि भोजन और टिड्डे की गंध को जोड़ा जाय तो ये मस्तिष्क की गतिविधि से जुड़कर अपेक्षा से कहीं अधिक तेज होती है। शोधकर्ताओं ने शोध में बताया कि यह प्रभाव केवल झुंड में रहने वाले टिड्डे में पाया गया।

इसका मतलब यह है कि टिड्डे झुंड में रहने वाली जीवन शैली अपनाने पर अपनी गंध की भावना को ढाल लेते हैं। अब उनकी घ्राण प्रणाली झुंड की मिश्रित गंध में भोजन की गंध को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। यही कारण है कि टिड्डे अभी भी झुंड में भोजन को आसानी से समझ सकते हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, वे कैल्शियम इमेजिंग प्रयोगों और कम्प्यूटेशनल विश्लेषणों को मिलाकर इस बात को बेहतर ढंग से समझने में सफल रहे हैं कि टिड्डे नई पयाज्वरणीय परिस्थितियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा उन्हें विश्वास है कि भावी शोध और विकास से भविष्य में होने वाले प्रकोपों को समझने, उनका पूर्वानुमान लगाने और उनका प्रबंधन करने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। शोध के परिणाम नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में प्रकाशित किए गए है।

कृषि व खाद्य अनुसंधान में भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं गरीब देशों के वैज्ञानिक

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जिन देशों पर जलवायु का सबसे अधिक असर पड़ता है, जहां भूख की दर सबसे अधिक है, उनका कृषि व खाद्य अनुसंधान में भागीदारी काफी कम है। रिपोटज में कहा गया है कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई और निवेश में वृद्धि की जरूरत है। कृषि खाद्य प्रणालियों पर अनुसंधान के लिए क्षेत्र की स्थिति को लेकर रिपोर्ट कहती है कि आठ में से केवल एक शोध पत्र 81 सबसे गरीब देशों के वैज्ञानिकों द्वारा लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) और अमेरिकी कृषि सहयोग संस्थान (आईआईसीए) के शोधकर्ताओं ने बताया कि कुछ देशों के पास 1,000 से भी कम अध्ययनों के साक्ष्य हैं।

बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए भविष्य के शोधों के मुद्दों को आकार देने के लिए तैयारी: रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 से 2023 तक के 63 लाख वैज्ञानिक शीर्षकों, सार और मेटाडेटा का आकलन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया। अध्ययन वर्तमान परिणामों का अवलोकन प्रदान करता है और दाताओं और सरकारों के साथ बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए भविष्य के शोध के मुद्दों को आकार देने के लिए तैयार है।

रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिनमें दुनिया के सबसे गरीब देशों में शोध के प्रयासों को समर्थन देने के लिए वित्त पोषण बढ़ाने की मांग शामिल है। साथ ही इसमें जलवायु परिवर्तन और भूख के प्रति सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कृषि अनुसंधान पद्धतियों में महिलाओं के नजरिए को शामिल करने, कृषि से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने तथा भागीदारी को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया है।

खाद्य प्रणालियों के भीतर समावेशी और न्यायसंगत विकास: अध्ययनकर्ता ने अध्ययन के हवाले से कहा, यह रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान को जरूरी नीतियों के साथ जोड़ती है, जो कम और मध्यम आय वाले देशों में खाद्य प्रणालियों के भीतर समावेशी और न्यायसंगत विकास को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित सुझावों और हस्तक्षेपों पर आधारित है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछले दशक में कृषि और खाद्य प्रणालियों में शोध प्रकाशनों में 60 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें अकेले कृषि से संबंधित 35,000 से अधिक जर्नल और तकनीकी रिपोर्ट शामिल हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन, अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे देशों द्वारा कृषि अनुसंधान प्रकाशनों में प्रभुत्व, असमान रूप से कम अनुसंधान वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देने की बात कही गई है।

पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय से 03 दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य

मुर्गी, भेड़, बकरी-सुकर पालन के लिए सरकार देती है 50%अनुदान

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन के लिए देश के युवाओं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को बैंक लोन सहित फॉर्म स्थापित करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

पशु पालन एवं डेयरी विभाग की योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2021 से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुख्यत: पशु नस्ल विकास तथा उद्यमिता विकास की गतिविधियों को शामिल कर बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण कुक्कुट पालन, भेड़ व बकरी पालन, सूकर पालन, साइलेज उत्पादन, फॉडर ब्लॉक तथा टोटल मिक्सड राशन के उत्पादन के लिए ऋण एवं अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार देती है अनुदान

एमपी के अनूपपुर जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. एपीपटेल ने बताया है कि इच्छुक हितग्राहियों/उद्यमियों को बैंकों से 50 प्रतिशत का ऋण एवं भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान राशि हितग्राहियों/उद्यमियों को समान 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने पर तथा दूसरी किस्त परियोजना पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा सीधे ऋणदाता बैंक को उपलब्ध करायी जाती है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक ने बताया है कि 50 लाख लागत के पोल्ट्री फार्म 1000 पक्षी, हैचरी तथा मदर यूनिट की संयुक्त इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख का अनुदान दिया जाता है। 01 करोड़ लागत के 500+25 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 50 लाख का अनुदान, 80 लाख लागत के 400+20 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 40 लाख का अनुदान, 60 लाख लागत के 300+15 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख का अनुदान, 40 लाख लागत के 200+10 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 20 लाख का अनुदान, 20 लाख लागत के 100+5 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाता है। 60 लाख लागत के 100+10 सूकर इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख का अनुदान तथा 30 लाख लागत के 50+5 सूकर इकाई के लिए अधिकतम 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

कैसे मिलेगा अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ.एपी पटेल ने जिले के बेरोजगार युवकों से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उद्यम स्थापित करने के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करते हुए आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होता है। योजना का लाभ व्यक्तिगत, स्वसहायता समूह, एफपीओ, एफसीओ और जेएलजी ले सकते हैं, जिसके लिए पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय से 03 दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

बरसात में कैसे करें मुर्गियों की देख भाल, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

भोपाल। जागत गांव हमार

बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब पशुपालन से जुड़े किसानों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बरसात में मवेशी और पक्षियों के बीच तेजी से संक्रमण फैलता है। इससे उनकी मौत भी हो जाती है। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, तो आपको उनकी देखभाल में अधिक सर्तकता बरतनी चाहिए।

जलभराव और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की जरूरत- बरसात में जलभराव के कारण कीचड़ और कचरे के सड़ने से बहुत ही दुर्गंध पैदा होती है। इससे मुर्गियों में कई तरह के रोग पनपते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में मुर्गियों की बिल्कुल साफ-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। यदि आपने पॉलट्री फॉर्म खोल रखा है, तो उसके अंदर भी हमेशा सफाई रखें। इसके अलावा उनके खान-पान पर भी ध्या दें। इससे मुगिज़्यों को होने वाली संक्रमित बीमारियों से बचाया जा सकता है।

इस तरह का दें आहार

बरसात के मौसम में उमस और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसके चलते मुर्गियों के चारे में फंगस लगने और कीड़े पनपने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि वे संक्रमित चारे खाते हैं, तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ऐसे में मुर्गियों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके आहार में नमी की मात्रा न हो। संभव हो, तो उनके आहार को धूप या हवा में सूखा दें। मच्छर और मक्खियों से भी संक्रमण फैलता है। बरसात में इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में इनके काटने से मुर्गियां बीमार भी पड़ सकती हैं। इसलिए मच्छर और मक्खियों से बचाने के लिए मुर्गियों के बाड़े में प्लास्टिक शीट या पर्दा लगा दें। साथ ही बाड़े के आसपास बारिश के पानी को नहीं जमने दें। क्योंकि जमे हुए बारिश के पानी में कई कीड़े और परजीवी का विकास होता है। इससे मुर्गियों में संक्रमण फैल सकता है।

टीकाकरण भी जरूरी

मुर्गियों को गर्माहट ज्यादा पसंद है। ऐसे में उन्हें नमी वाली जगहों पर नहीं रखें। इस जगह को जितना सूखा रखेंगे, मुर्गियां उतनी ही सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा बारिश का मौसम मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। इसलिए बैक्टीरिया और वायरस से उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण भी जरूरी है।

सूअर के लिए घातक डायरिया पालक समय रहते करें बचाव

भोपाल। जागत गांव हमार

सूअर पालन में कई ऐसी चुनौतियां हैं, जो सुअर पालन को मुश्किल बना देती हैं और इस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इनमें से ही एक है सुअरों में होने वाला 'डायरिया' या 'दस्त' जिसका सीधा असर सुअर पालन पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर सूआरों को डायरिया हो जाए तो फिर पालकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। सूअरों में डायरिया अपर्याप्त वजन बढ़ोतरी और मृत्यु की एक बड़ी वजह है। एक रिपोर्ट की मानें तो 10 से 70 प्रतिशत तक सूअरों में मौत का कारण डायरिया ही होता है। डायरिया ज्यादातर स्तनपान करने वाले सूआर शावकों और हाल ही में दूध छुड़ाए गए शावकों में होता है। इसकी वजहों में बैक्टीरिया खासतौर पर ई कोलाई, वायरस और कई तरह के परजीवी जैसे कारण सबसे ऊपर होते हैं।

इन दवाइयों से मिलेगी मदद - सूआर को डायरिया न हो इसके लिए निवारक और रोकथाम के उपायों का अपनाया जाना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से इस बीमारी को रोका जा सकता है। जिन शावकों को दस्त हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं जैसे एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलैनेट, कोलिस्टिन, सल्फोनामाइड्स-ट्राइमेथोप्रिम, एनरोफ्रलोक्सासिन, सेफ्रिटयोपफर, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन आदि का प्रयोग शामिल है। किसी खास एंटी-बायोटिक के बार-बार और लंबे समय तक प्रयोग से उस विशिष्ट एंटीबायोटिक के खिलाफ 'एंटीबायोटिक इम्युनिटी' या 'एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स (एएमआर)' डेवलप हो जाती है। इस वजह से कभी-कभी एंटीबायोटिक अप्रभावी हो सकती हैं।

आहार में जरूरी एसिड्स

सुअरों के आहार में आर्गेनिक एसिड्स का मिश्रण देने से डायरिया के वायरस ई. कोलाई की संख्या में कमी आती है। साथ ही यह फायदेमंद लैक्टोबैसिलस की संख्या में इजाफा भी करते है। ऑर्गेनिक एसिड्स कमजोर होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाते हैं जैसे-सेब में ऑर्गेनिक एसिड्स, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड, नीबू में साइट्रिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड का प्रयोग सुअरों में एंटीबायोटिक दवाओं के ऑप्शन के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, ऑर्गेनिंग एसिड, साइट्रिक एसिड भी सूअर पालन में फायदेमंद साबित हुए हैं।

पशुओं के लिए जानलेवा होते हैं पेट के कीड़े, जानें लक्षण-बचाव का उपाय

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों के लिए गाय पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जिससे उन्हें दूध, खाद और अन्य कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय पालन विशेष माना जाता है, क्योंकि यह कई लोगों के लिए कमाई का मुख्य साधन होता है। ऐसे में जरूरी होता है कि उनका दूध उत्पादन ठीक ठाक बनाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। पशुओं के पेट में कीड़े पड़ना एक सामान्य बीमारी होती है, यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये काफी गंभीर बन सकती है। कीड़े पड़ने पर पशु का कुछ खाने पीने पर कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि भोजन का पेट में जाने के बाद कीड़े चट कर जाते हैं। इससे पशु के स्वास्थ्य पर भारी असर होता है और पशुपालकों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

समय रहते करें इलाज- पशुपालक पशु के पेट में कीड़े पड़ने की समस्या की जल्द से जल्द पहचान कर लेनी चाहिए, जिससे समय रहते जानवर को इस समस्या से निजात मिल जाए और आपका भी आर्थिक नुकसान होने से बच जाएं। इसके लिए पशुपालकों के पास जानवार के पेट में होने वाली कीड़ों की समस्या की सही जानकारी होनी चाहिए। यदि पशु का समय रहते इलाज करवा लिया जाता है, तो इससे नुकसान लगभग 30 से 40 फीसदी तक कम हो सकता है।

पशु के पेट में कीड़े होने पर लक्षण

-पशु के मिट्टी खाने पर
-कमजोरी दिखाई देने पर
-मटमैले रंग का बदबूदार दस्त आने पर
-गोबर से काला खून या कीड़े दिखाई देने पर
-पशु में खून की कमी होने पर
-दुधारु पशु के दूध उत्पादन में कमी होने पर

पशुओं का कीड़ों से बचाव

पशुपालकों को अपने जानवारों के पेट में कीड़े की बिमारी होने पर समय रहते इसकी पहचान करके इसका उपचार कर लेना चाहिए। इसके बचाव के लिए पशु को हर 3 महीने में डीवेरमैक्स की दवा देनी चाहिए। लेकिन इस दवा के देने से पहले आपको अपने पशु के गोबर की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। पशु का वैक्सीनेशन कराने से पहले आपको उन्हें आंत के कीड़ों की दवा जरूर देनी चाहिए। टीकाकरण होने के बाद आपको पशु को कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए। जितना हो सकें अपने पशु को शुद्ध चारा, दाना खिलाएं और उन्हें साफ पानी पिलाएं।

बिना कार्ड के नहीं मिलेगा कोई लाभ, जानें आवेदन करने की प्रक्रिया

सरकारी सुविधा लेने के लिए किसानों को कराना होगी फार्मर रजिस्ट्री, मिलेगा कार्ड

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत सरकार के द्वारा किसानों की मदद के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जाती हैं, जिसकी तहत किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें, लेकिन अब से किसानों को सरकार की किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना जरूरी होगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है और यह कैसे काम करता है। बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा, जिसकी मदद से आप सरकारी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जुलाई माह में ही इस योजना की औपचारिक रूप से लॉन्च कर दी जाएगी।

क्या है फार्मर रजिस्ट्री- फार्मर रजिस्ट्री में किसान से जुड़ी सभी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होती है। इसमें किसानों के भूलेख डाटाबेस को एक साथ करके बकेट तैयार किया जाता है। ताकि किसानों की सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सके। फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद किसान की एक यूनिक आईडी बनती है और साथ ही एक गोल्डन कार्ड भी बनाया जाता है। इस कार्ड में किसान की सभी जानकारी होती है।

फार्मर रजिस्ट्री के बाद मिलेगी ये सभी सुविधा

किसान की फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद वह सरलता से फसली ऋण, फसली बीमा, आपदा राहत, परामर्श आदि सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। ये ही नहीं बल्कि दिसंबर में जारी होने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का लाभ भी उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा किया होगा।

फार्मर रजिस्ट्री के लिए कमेटी का गठन

सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए एक जिला कमेटी का गठन किया, जिसमें डीएम कि अध्यक्षता में 11 सदस्यीय शामिल हुए। इसके अलावा इसके लिए सीडीओ उपाध्यक्ष व उपनिदेशक कृषि सचिव के साथ तहसील स्तर पर कमेटी बनाई गई। फार्मर रजिस्ट्री के लिए जिला स्तर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी व सभी तहसीलदारों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण भी दिया गया। ताकि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसान को बार-बार कागजात सत्यापन के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा।

हर दिन 18-19 हजार किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य

फार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकार ने हर दिन करीब 18-19 हजार किसानों का रजिस्ट्रार का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों का फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन हो सके और किसान भी सरलता से अपने ही गांव में पंजीयन करवा सके।

फार्मर रजिस्ट्री के लिए कागजात

फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीयन करने के लिए उनका आधार नंबर खतौनी मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके बाद ही किसान को एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। फिर जब किसान की पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। किसान को एक गोल्डन कार्ड प्राप्त होगा। जिसकी मदद से किसान को सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा।

समस्या निराकरण के लिए हरदा में मूंग उपार्जन के लिए बनाया गया जिला स्तरीय कंट्रोल रूम

हरदा। जागत गांव हमार

शासन के निर्देश अनुसार कृषि विपणन वर्ष 2024-25 के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केन्द्रों की स्थापना की गई है। उप संचालक कृषि संजय यादव ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केन्द्रों पर आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिये जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम में सहायक संचालक कृषि रामकृष्ण मंडलोई मोबाइल नम्बर 9926490984, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी गोविन्द प्रसाद सोनी मोबाइल नम्बर 9926312392 तथा तकनीकी सहायक तुलसीराम बरबड़े मोबाइल नम्बर 9926985277 की ड्यूटी लगाई गई है।

उपसंचालक यादव ने निर्देशित किया है कि अधिकारी कर्मचारी कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 बजे से सायं 6 बजे तक अपने दूरभाष पर प्राप्त किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा शिकायत पंजी का संधारण करेंगे।

10 जुलाई तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

एमपी सरकार की नई पहल अब युवा करेंगे फसलों की गिरदावरी का काम

भोपाल। जागत गांव हमार

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सहित सरकार की बहुत सी योजनाओं में फसलों की गिरदावरी की जाती है। ऐसे में किसानों की फसलों की सटीक गिरदावरी की जा सके इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नई पहल शुरू की है। इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार फसलों की गिरदावरी के लिए अब युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं।

फसलों की मध्यप्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी कार्य वर्ष में 03 बार यानि खरीफ, रबी और जायद सीजन में सारा एप के माध्यम से की जाती है। जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है।

फोटो खींचकर किया जाएगा सर्वे- फसल गिरदावरी के काम में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह प्रत्येक मौसम के लिए लगभग 45 दिन की कार्रवाई होती है। जिसमें जिओ फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। इस योजना में मौसम खरीफ-2024 डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के लिए सर्वेयर पंजीयन 10 जुलाई तक किया जाना है।

आवेदन कहां करें

फसलों की गिरदावरी का काम करने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक युवा गांव के स्थानीय/निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो एमपी भूलेख पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें आधार ओटीपी से पंजीकरण भू-लेख पोर्टल के माध्यम से होगा पटवारी द्वारा ग्राम आवंटन किया जाएगा। युवा द्वारा सारा एप के माध्यम से कार्य संपादित किया जायेगा। जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है तथा उनके पास मोबाईल फोन मय इंटरनेट उपलब्ध होना जरूरी है। पंजीयन कार्य हेतु युवाओं को निर्धारित राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

पन्ना जिले में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित

पन्ना। जागत गांव हमार

भारत और मध्यप्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 वर्ष एवं अधिक आयु के कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेकर स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इस योजना में बैंक से प्रदान ऋण में उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत राशि का 35 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 10 लाख रुपए जो भी कम हो स्वीकृत किया जाता है। स्वरोजगार के इच्छुक उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर दाल मिल, आटा मिल, चावल मिल, बरी, पापड़, अचार, मुरब्बा जैम, जेली, केचप, सिरका, ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट, कुरकुरे, चिप्स आदि किसी भी प्रकार की इकाई स्थापित कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग के जिला कार्यालय अथवा विकासखंड में स्थापित उद्यानिकी रोपणी में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्यमी को बैंक ऋण दिलाने में सहयोग के लिए विकासखंड स्तर पर जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति भी की गई है।

कमिश्नर ने बताई किसानों के लिए फर्टिलाइजर मोबाईल एप्प की खूबी

नीमच। जागत गांव हमार

जिला कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्शन में नीमच जिले में सहकारिता विभाग के माध्यम से तैयार करवाये गये फर्टिलाइजर की मांग एवं वितरण के मोबाईल एप्प का सजीव प्रजेन्टेशन संभाग आयुक्त संजय गुप्ता ने गत दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में देखा। इस मोबाईल एप्प का प्रजेन्टेशन सहायक आयुक्त सहकारिता राजू डाबर ने दिया। कलेक्टर दिनेश जैन ने फर्टिलाइजर एप्प की विशेषताओं से संभाग आयुक्त को अवगत कराया। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने कहा, कि किसानों की सुविधा के लिए तैयार यह फर्टिलाईजर मोबाईल एप्प प्रदेश में अपनी तरह का पहला नवाचार है। यह एप्प किसानों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने फर्टिलाईजर एप्प की विशेषताओं को बारीकी से समझा और इस एप्प में शेष रहे किसानों को भी जोड़ने तथा किसानों को एसएमएस की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

ये रहे उपस्थित- इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, एडीएम लक्ष्मी गामड़, सभी डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, राजस्व अधिकारी, उप संचालक, कृषि भगवान सिंह अर्गल, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आरपी नागदा भी मौजूद थे।

खंडवा में मछली पालन पट्टा के लिए 16 तक आवेदन

खंडवा। जागत गांव हमार

जनपद पंचायत पंधाना अंतर्गत स्थित सिंचाई जलाशय को मछली पालन के प्रयोजन के लिए पट्टे दिए जाना है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन 16 जुलाई तक कार्यालय जनपद पंचायत पंधाना में अवकाश दिनों को छोड़कर जमा कर सकते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना ने बताया कि यह पट्टे ग्राम अर्दला जलाशय के लिए दिया जाना है। उन्होंने बताया कि जलाशय पट्टे पर लेने के लिए कार्यक्षेत्र/जलक्षेत्र की मछुआ सहकारी समितियों को पहली प्राथमिकता होगी तथा प्राथमिकता क्रम पर वंशानुगत मछुआ जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वगऱ्, सामान्य वगऱ् की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को यदि उस प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो, तो उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार स्वसहायता समूह, मछुआ समूह को लेकिन स्वसहायता समूह, समूह को आवश्यक होगा कि एक वर्ष में समिति पंजीकृत कराएं। सीईओ ने बताया कि जलाशय पट्टा आवंटन की दशा में प्रारंभिक पट्टा राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग को आवश्यकता होने पर मत्स्य प्रजनक अनिवार्यत: उपलब्ध कराने होंगे जिसके लिए विभागीय दर अनुसार मत्स्य विभाग द्वारा देय होंगे। अन्य आवश्यक शर्तें जनपद पंचायत पंधाना या मत्स्य विभाग कार्यालय से कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में देखी जा सकती है।

दोस्तों की सलाह पर प्राइवेट नौकरी छोड़ी, शुरू की जैविक खेती

हर महीने एक लाख रुपए की कमाई अब 800 किसानों को दे रहे ट्रेनिंग

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बैरसिया में एक युवक ने 10 हजार रुपए महीने की प्राइवेट नौकरी छोड़कर आधुनिक तरीके से जैविक खेती शुरू की। अब 4 से 5 लोगों को रोजगार देने के साथ ही हर महीने एक लाख रुपए कमा रहा है। जिले के 800 किसानों को स्मार्ट खेती की ट्रेनिंग भी दे रहा है। स्मार्ट किसान सीरीज में इस बार बात बैरसिया के गोलखेड़ी गांव में रहने वाले किसान श्याम कुशवाह की। श्याम 12 एकड़ में खेती कर रहे हैं। करीब ढाई एकड़ में अमरूद के पेड़, एक एकड़ में पालक और बाकी साढ़े 8 एकड़ में गेहूं समेत दूसरी फसल लगाई है। इससे उन्हें एक साल में करीब 12 लाख रुपए का लाभ हो जाता है।

श्याम ने कहा कि साल 2015 से पहले पिता पारंपरिक खेती करते थे। 12 एकड़ में गेहूं, चना और सोयाबीन की अच्छी क्वालिटी का बीज बोते थे। सालभर हाड़तोड़ मेहनत करते थे। फिर जब फसल काटकर हिसाब लगाते थे, तो सालभर की आय एक से डेढ़ लाख रुपए ही होती थी। इस तरह पिता जी खेती को घाटे का सौदा मान चुके थे। उस समय मैं बीसीए करके 10 हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहा था। सैलरी भी ज्यादा नहीं मिलती थी, इसलिए सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि कमाई अच्छी हो जाए। फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊं। फिर कुछ दोस्तों ने आधुनिक तरीके से खेती की सलाह दी। इसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉब छोड़कर जैविक तरीके से खेती करने का फैसला किया। ये बात माता-पिता और बड़े भाइयों को बताई, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर रिक्वेस्ट करने पर पुश्तैनी जमीन पर खेती करने की अनुमति दे दी।

पहली बार में ही अमरूद की खेती से मुनाफा

श्याम ने बताया, जुलाई-2016 में पहली बार उद्यानिकी विभाग के अफसरों से मिला। उनको जमीन के बारे में बताया। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने अमरूद का बगीचा लगाने की सलाह दी। साथ ही, बगीचे के लिए अमरूद के पौधे नि:शुल्क दिए। इन पौधों को ढाई एकड़ में रोप दिया। सालभर पौधों की देखभाल करने के साथ ही खाद, पानी दिया। पहली साल पौधों में फल कम लगे। बावजूद इसके 45 हजार रुपए का मुनाफा अमरूद के बगीचे से हुआ। मुनाफा कम हुआ, लेकिन उम्मीद थी पौधे बड़े होंगे तो फल ज्यादा लगेंगे और मुनाफा बढ़ेगा। अगले साल अमरूद की फसल बेचकर ढाई लाख रुपए कमाए, जो पारंपरिक खेती की इनकम से एक लाख रुपए ज्यादा थी। अमरूद की खेती से मुनाफा होने लगा, तो मैंने पपीता, चीकू और आम के 10-10 पौधे लगाए। साथ ही, खाद की लागत कम करने के लिए गोबर से जैविक खाद बनाना शुरू किया। साल दर साल खेती में इनकम बढ़ने लगी। फिर सरकार से सब्सिडी लेकर 33 लाख रुपए की लागत से पॉली हाउस बनवाया। इसमें करीब 19 लाख रुपए खर्च हुए। बाकी 14 लाख रुपए सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिया।

पॉली हाउस में नहीं होता पॉलीराइजेशन

साल 2018 में पॉली हाउस में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर पहली बार 45 हजार रुपए की लागत से शिमला मिर्च लगाई, लेकिन फसल खराब हो गई। खाद-बीज का पैसा डूब गया। 45 हजार रुपए का घाटा हुआ। मां, पिता और भाइयों ने डांटा, लेकिन खेती करना बंद नहीं किया। फिर बैरसिया रोड पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में विशेषज्ञों से मिला। तब पता चला कि पॉली हाउस में लगाई शिमला मिर्च को वायरस लग गया था। इसके चलते शिमला मिर्च का आकार छोटा रहा। मैंने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करने के बाद टमाटर की भी खेती की। इसमें भी घाटा हुआ। एक एकड़ के पॉली हाउस को बनाने में बड़ी रकम खर्च करने के बाद लगातार हो रहे घाटे का कारण उद्यानिकी विभाग के अफसरों से पूछा। तो पता चला - पॉली हाउस में भंवरा, मधुमक्खी के नहीं पहुंचने के कारण परागकणों का पॉलीराइजेशन नहीं हो पाता है। इस कारण पॉलीहाउस में पॉलीराइजेशन वाली फसलों की खेती नहीं की जाती है।

न फूल, न फल चुनी पत्ती वाली फसल

विशेषज्ञों की सलाह पर पॉली हाउस में फूल और फल वाली फसल की खेती बंद कर दी। साथ ही, पत्ती वाली फसल पान और पालक की खेती शुरू की। जुलाई से सितंबर के बीच पॉली हाउस में लगाई पालक से पहली बार साल 2018 में 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तब से लगातार पॉली हाउस में पालक की खेती कर रहा हूं। अब मैं 12 एकड़ जमीन को तीन अलग-अलग सेक्टर में बांटकर मिक्स खेती कर रहा हूं। इससे सालाना 12 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है।

मार्च से शुरू करते हैं पालक की खेती की तैयारी

पालक की खेती के लिए पॉली हाउस के खेत को हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में खाली कर देते हैं। मार्च से खेत को तैयार करना शुरू कर देते हैं। खेत में सबसे पहले प्लाऊ चलाते हैं। इसके बाद करीब एक हफ्ते तक खेत को खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद जैविक खाद खेत में डालते हैं, जो गोबर और वर्मी कंपोस्ट तकनीक से बनी होती है। खेत में खाद डालने के एक से दो दिन बाद रोटावेयर से क्यारी बनाते हैं। इसके बाद अगले एक महीने तक खेत को खाली छोड़ देते हैं। जून के दूसरे और तीसरे हफ्ते में खेत में पालक का बीज डालते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में पालक की पहली फसल काटते हैं।

क्यारी बनाकर करते हैं पालक के खेत की सिंचाई

पालक के खेत और अमरुद के बगीचे की सिंचाई के लिए अलग से सिंचाई व्यवस्था नहीं बनाई है। पालक के खेत में पानी सामान्य फ्लो से सीमित मात्रा में पहुंचे, इसके लिए मेढ़ को थोड़ा ऊंचा करके पतली नाली बनाई है। जब पालक की एक क्यारी की सिंचाई हो जाती है, तो अगली क्यारी में पानी भरते हैं। इस दौरान पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं करते, ताकि पालक जड़ से उखड़कर पानी में न बहे। वहीं, अमरुद के बगीचे की सिंचाई के लिए खेत में पाइप लाइन बिछाई है, ताकि प्रत्येक पेड़ के नीचे बिना किसी परेशानी के पानी पहुंच सके।

26 बोर कराए, चार में निकला पानी

खेती के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था करने के लिए खेत में 4 ट्यूबवेल बनवाए हैं। इन चार ट्यूबवेल के लिए खेत में 26 स्थानों पर बोरिंग कराई थी, लेकिन 22 बार ट्यूबवेल के खनन में पानी नहीं निकला था। श्याम सिंह कहते हैं कि वर्तमान में खेत में पानी की मौजूदगी की स्थिति यह है कि एक भी ट्यूबवेल को दो घंटे से ज्यादा समय तक चलाने पर पानी का फ्लो टूट जाता है।

पालक को वायरस से बचाने 10 पत्ती काढ़े का छिड़काव

पॉली हाउस में खड़ी पालक की फसल को कीट और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने 10 पत्ती काढ़े का छिड़काव करते हैं। यह काढ़ा खेत में ही खुद बनाता हूं। इस काढ़े में आक, नीम, बेशरम सहित ऐसे पौधों की पत्तियां लेते हैं, जिन्हें बकरी नहीं खाती हैं। यह काढ़ा एक ड्रम में 10 दिन में तैयार होता है। इसके छिड़काव से फसल में रोग नहीं लगता। मैं खेतों में केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करता हूं। सभी खेतों में जैविक खाद का ही इस्तेमाल करता हूं। इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा महीने दिसंबर होता है। सही वातावरण में पालक की बुवाई साल भर की जा सकती है। पालक की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बुवाई जनवरी-फरवरी, जून-जुलाई और सितंबर-अक्टूबर में की जा सकती है, जिससे पालक की अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। पालक की खेती को खरपतवारों से 60 फीसदी की हानि होती है, इसलिए पालक से अच्छी आमदनी कमाने के लिए इन्हें खरपतवारों से बचाना चाहिए। पालक की बुआई करने के तुरंत बाद पेंडीमेथिलिन का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब खेत में नमी बनी रहे तब इसका छिड़काव करें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया शुभारंभ

हमारी देशी गौ-माता सर्वश्रेष्ठ

-गौ-माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्यप्रदेश सरकार कृत-संकल्पित

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार किसानों को गेहूं, चने आदि अलग-अलग फसलों के लिए बोनस दिया जा रहा है, उसी प्रकार अब दूध खरीदने पर भी बोनस दिया जाएगा ताकि लोग घर-घर गौ-माता को पालने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। वहीं दुर्घटनाग्रस्त व दिव्यांग गौ-माताओं को गौ-शाला में रखा जायेगा। दूध का व्यवसाय भी हमारे लोगों का जीवन बदलने में सहायक हो इसका प्रशिक्षण भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हमारी देशी गौ-माता सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी देशी गौ-माता के संवर्धन के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के ग्राम रबाखेड़ी स्थित कपिला गौ-शाला के संवर्धन और एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौ-शाला में पौध-रोपण कर संपूर्ण जिले में अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कपिला गौ-शाला का भ्रमण कर अवलोकन किया। उन्होंने गौ-शाला में गौ-माता का पुष्पमाला पहनाकर, तिलक लगाकर पूजन किया और आरती उतारी। उन्होंने नन्हे बछड़ों को पशु चारा खिलाकर दुलार भी किया। उन्होंने गौ-शाला में उपलब्ध आधुनिक पशु चारा मशीन सहित अन्य उपकरणों का अवलोकन किया। कपिला गौ-शाला के अच्युतानंद महाराज ने गौ-शाला में किए गए नवाचार के साथ गौ-शाला संवर्धन के मास्टर प्लान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पौध-रोपण और उसके संरक्षण की संकल्प लेने वाले विभिन्न संस्थाओं को पौधे भेंट किया। कार्यक्रम में कपिला गौ-शाला की विकास कार्ययोजना पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्वामी मुस्कुराके ने किया। गायक श्री अमित शर्मा द्वारा देशभक्ति और पर्यावरण केंद्रित सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेडा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, जनपद अध्यक्ष कमला कुंवर, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

गाय चराचर जगत की माता

मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 पुत्रों की बजाय अगर एक गौ-माता हो तो उसका महत्व 10 पुत्रों से बढ़कर होता है। हमारे यहां कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः यानी गाय चराचर जगत की माता हैं। गौ-माता की सेवा से योगीराज श्रीकृष्ण, गौ-पालक गोपाल कृष्ण के रूप में विख्यात हुए। हमारी गौमाता भारतीय सनातन संस्कृति की प्राण हैं। गंगा, गीता, गायत्री, गोवर्धन और गोविंद की तरह ही परम पूज्य हैं हमारी गौमाता। सर्वदेवमयी हि गौः गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास माना जाता है। गौ-माता की सेवा से सभी देवी-देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है।

गौ-माता भगवान शंकर और विष्णु की प्रतीक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पद्म पुराण में कहा गया है कि गौ-माता के मुख में चारों वेदों का वास है। गाय की सींग में ही भगवान शंकर और विष्णु का वास है। इस विशेष पहचान से गौ माता हमारी प्रकृति में अद्वितीय छटा बिखेरती हैं। सच्चे अर्थों में गौ माता हमारे जीवन को चरितार्थ करते हुए स्पंदन देने का काम करती है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो उन्हें जन्म देने वाली माता देवकी थीं, पालने-पोसने वाली यशोदा और उन्हें गोपाल बनाने वाली हमारी गौ-माता हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान कृष्ण के जन्म और लालन-पालन में माता यशोदा और नंद बाबा के पराक्रम और पुरुषार्थ का भी उल्लेख किया।

कान्हा का जीवन गायों के बिना है अधूरा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-माता की महिमा देखिए कि भगवान भोलेनाथ शिव और हमारे गोपाल कृष्ण ने गौ-वंश को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। भोलेनाथ ने नंदी को अपना वाहन बनाया तो हमारे कान्हा का जीवन ही गायों के बिना अधूरा है। सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण के साथ गौ-माता के जोड़ने से ही वे योगीराज श्री कृष्ण गोपाल कहलाएं। जो भगवान कृष्ण को भी आनंद से भर देता है। हमेशा उन्होंने अपनी पहचान गौ-माता से बनाकर रखी। गोपाल से गाय माता का जोड़ने का अर्थ यह है कि प्रकृति से प्रेम, मूक प्राणियों के प्रति प्रेम और 33 करोड़ देवी देवताओं की छत्र छाया है।

कपिल गौ-शाला के संवर्धन के कामों को सराहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि काल के प्रवाह में हमारी गौ-माता पर भी संकट आया है। सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ गौ-माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कृत-संकल्पित है। गौ-शालाओं को संवारने का काम किया जा रहा हैं। उन्होंने कपिला गौ-शाला के संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अच्युतानंद का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि महाराज गौ-वंश में संरक्षण के दिशा में महती भूमिका निभा रहे हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने पहले भी ग्वालियर में 5000 से अधिक गौ-वंश के पालन-पोषण का उल्लेखनीय काम किया हैं। उन्होंने कपिल गौ-शाला में निर्मित भगवान शिव गणेश की सुंदर प्रतिमाओं की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपिला गौ-शाला में न केवल पशुओं का अच्छे से पालन-पोषण किया जा रहा है, बल्कि यह आधुनिक यंत्रों से भी सुसज्जित है। यहां चंद मिनटों में 1000 से अधिक पशुओं का आहार बनाया जा सकता हैं। उज्जैन, भोपाल, इंदौर देवास आदि के प्रमुख मार्गों पर निराश्रित पाए जाने वाले गौ-वंश को गौ-शाला में रखने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कपिला गौ-शाला के संवर्धन के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

गौ-वंश का संरक्षण सभी का दायित्वः अच्युतानंद

कपिला गौ-शाला के अच्युतानंद महाराज ने कपिला गौ-शाला के संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव, जिला प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि गौ-वंश का संरक्षण केवल सरकार का नहीं हम सभी का दायित्व हैं। श्री अच्युतानंद जी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को गौ-शाला में उत्पादों से बने भगवान शिव और गणेश की प्रतिमा भी भेंट की।

मध्यप्रदेश नई इबारत लिख रहाः सांसद

सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से कपिला गौ-शाला का स्वरूप बदला हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रदेश को नित्य नई-नई सौगातें मिल रही है। धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्रों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। सांसद फिरोजिया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी से अपनी मां के नाम पर रोपा।

सभी वर्गों का हो रहा विकासः विधायक

विधायक अनिल जैन कालूहेडा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से कपिला गौशाला को ए प्लस कैटेगोरी में बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौ-शालाओं का समग्र रूप से संवर्धन का काम भी जारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इंदौर से महाकाल तक मेट्रो की सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उज्जैन का पूरा परिक्रमा पथ अब 8 लेन का होगा और 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रमुख मार्ग फोर लेन होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सभी वर्गों का समान रूप से विकास किया जा रहा हैं।

कार्यक्रम की अन्य झलकियां

- मुख्यमंत्री ने पौधारोपण और उसके संरक्षण का संकल्प लेने वाले 11 विभिन्न संस्थाओं को पौधे भेंट कर प्रेरित किया।
- मुख्यमंत्री को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा कपिल गौशाला में बने गो उत्पादों को स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट किया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ पोस्टर का विमोचन किया गया।
- कार्यक्रम में भरत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री के खेती किसानी के प्रतीक हल को भेंट किया।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव को श्री गोपाल सिंह जाट द्वारा भगवान बालाजी की प्रतिमा भेंट की गई।
- कपिला गौ-शाला को बनाया जाएगा आदर्श गौशाला, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगी।
- उज्जैन जनपद के ग्राम र खेड़ी स्थित कपिला गौ-शाला को जन-सहयोग से आदर्श गौशाला बनाया जा रहा हैं।
- कपिला गौ-शाला अपने आप में पहली गौ-शाला होगी जो आने वाले समय में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी। इस गौ-शाला में 2500 गौ-वंश का पालन पोषण हो सकेगा।

गौशाला में चार शेड बनाएंगे

कपिला गौ-शाला के संवर्धन की परियोजना के तहत गौशाला में चार शेड (24-60द्ध) बनाएं जाएंगे जिसमे प्रत्येक शेड की अनुमानित क्षमता 600 गोवंश की होगी। पशुओं को त्वरित उपचार के लिए यहां पृथक से शेड निर्माण कर औषधालय की व्यवस्था की जा रही हैं। वहीं पशु आहार के लिए भूसा भंडारण शेड (15-48द्ध) भी बनाया जा रहा हैं। गौ-सेवा शाला, बायोगैस संयंत्र,प्रशासनिक /कार्यालय भवन, प्रयोगशाला, डेयरी और आगंतुकों के लिए पार्किंग और उद्यान क्षेत्र भी गौ-शाला में विकसित किया जाएगा। वॉच टावर से गौ-शाला की निगरानी की जाएगी।

गो उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा

गौ-वंश को को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गौ-शाला को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त भूमि में गौ-वंश के लिए चरी बुवाई कर चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गोबर से कलर पेंट, गमले, गो-काष्ठ, गोबर कलाकृति आदि गो उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। गौशाला में सीएसआर के माध्यम से 14 लाख की मिक्सर मशीन, 10 लाख की लोडर ट्रैक्टर, 1 लाख की ह फिल्टर प्लांट की व्यवस्था की जा रही हैं। वहीं गौशाला में ट्रैक्टर सूपा, ट्रैक्टर ट्रॉली, पानी के टैंकर की व्यवस्था भी की गई है।

-सीएम ने एक पेड़ मां के नाम पौध-रोपण अभियान का किया शुभारंभ

भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व दस पुत्रों के समान माना गयाः सीएम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व दस पुत्रों के समान माना गया है। वनस्पति के साथ-साथ नदी, पहाड़ आदि को जीवंत मानना हमारी संवदेनशील सांस्कृतिक परम्परा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सरकार ने भी प्रदेश में वृहद पौध-रोपण का संकल्प लिया है। इस क्रम में प्रदेश में पांच करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इंदौर में 51 लाख, भोपाल और जबलपुर जिले में 12-12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जंबूरी मैदान पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम-वृहद पौध-रोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नेदीप प्रज्वलित कर एवं अपनी माताजी स्व. लीला बाई यादव की स्मृति में पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने जंबूरी मैदान में आंवले का पौधा लगाया। इससे पहले उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पर बनाए गए चित्रों का अवलोकन भी किया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)